1995, to help these very special citizens. The objective of the Act was to ensure level playing field through equal opportunities, full participation and protection of rights of the disabled persons. Apart from a few notable exceptions in private and public sector, these people still face huge deficit in the job market. The Act provides to reserve three per cent of jobs in all categories in the Government and public sector and to encourage the private sector to reserve five per cent jobs in all categories for such persons with special abilities. However, even after ten years, the objectives are yet to be realised. Crucial provisions of the Act have not been fully implemented. The incentives to encourage the companies to employ such citizens have not yet been formulated. The Government has still to formulate a National Policy for Disabled. I would like to ask the Government how many more months and years would be required to see the resolve of this Parliament being fructified. Or will it be crushed under the dreaded steel frame? Even if such a policy is drafted, who would ensure its honest and sensitive implementation at grass-root level? As a civilised society we have to respond to such questions.

श्री उपसभापति:श्री राम नारायण साहू। आप इसे lay कर दीजिए।

Concern over Decreasing Ground Water Level In the Country

श्री राम नारायण साहू (**उत्तर प्रदेश**):महोदय,हम सब अवगत हैं कि भूमिगत जल-स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। बड़े-बड़े पेड़ सूख रहे हैं। सरकारों द्वारा लगाए गए नलकूप सूख कर बेकार हो गए है। भूमिगत जल-स्तर पेड़ों की जड़ों एवं नलकूपों की पाइपों की पहुंच से नीचे चला गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि इसे रोका नहीं गया,तो 20 वर्षों बाद हरित क्षेत्र रेगिस्तान में बदल सकते हैं। आश्चर्य है कि सरकार समस्या के प्रति उदासीन क्यों हैं? हमें पूर्वजों से हरी-भरी मिली धरती को हम आने वाली पीढ़ी को रेगिस्तान बनाकर सौंपने की तैयारी में है। यह आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य ही होगा। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, इसलिए इस समस्या का ठोस कारण एवं निवारण की विस्तृत जानकारी माननीय सदन को नहीं दे सकता,परन्तु मैं समस्या की गंभीरता से भली-भांति अवगत हूँ और सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि वह समस्या को विकराल रुप धारण करने से पहले ही कोई ठोस कदम उठाए।

गिरता हुआ भूमिगत जल स्तर भाप,पानी और बर्फ के आनुपातिक संतुलन के बिगड़ने की ओर इशारा करता है,जो कि और भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है। मेरा मानना है कि भूमिगत जल का अंधाधुन्ध दोहन एवं बाढ़ से निपटने हेतु बिछाए गए जल-बहाव नालों के कारण ही इस

समस्या का जन्म हुआ है। इन नालों से तीव्र जल-बहाव के कारण भूमि को पानी सोखने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।अब भवनों पर वर्षा-जल को ऊपर ही रोक कर एकत्र करने से (रेन वाटर हार्वेस्टिग) विधि से समस्या और बढ़ सकती है। सरकार से अनुरोध है कि वैज्ञानिकों से विस्तृत जानकारी एकत्र करके सदन को भी उपलब्ध कराए एवं समस्या से निपटने हेतु ठोस कदम उठाए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy; absent.

Concern over issuing of Fake Identity Cards in some Parts of Gujarat and Rajasthan

श्री धर्मपाल सभ्रवाल (पंजाब):माननीय उपसभापति महोदय,मैं सरकार का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह अत्यधिक खेद की बात है कि देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नकली परिचय प्रमाण पत्र जिसे स्मार्ट कार्ड के नाम से जाना जा रहा है जारी किये जा रहे हैं।

ऎसी सूचना मिली है कि नकली चालक प्रमाण पत्र भी असामाजिक तत्वों को भी जारी किये गये हैं। इस बारे में कई एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई है जिसका कोई परिमाण नहीं निकला। जिस वजह से आतंकवादी शरणार्थियों के रुप में स्मार्ट कार्ड और चालक प्रमाण पत्र अपनी पहचान स्वरुप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्ड सरकार द्वारा नियुक्त एक कंपनी के द्वारा जारी किये गये हैं। इस बारे में एडवांस सूचना मिली है कि इस कंपनी ने अति संवेदनशील जानकारी (भारतीय सेना की कैन्टीन और खान-पान प्रबंधन की) विदेशों में मुहैया कराई है।

मेरा निवेदन है कि सरकार के द्वारा विस्तृत जांच कराई जाए। क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित को आघात पहुंचा रहा है। इसलिए स्मार्ट कार्ड और चालक प्रमाण पत्र के जारी किये जाने पर रोक लगानी चाहिये जब तक सरकार इस बारे में विस्तृत जानकारी हासिल न कर ले।

Demand to Expedite Process of giving IIT Status to Osmania University and Andhra University

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): Sir, the Expert Committee set up by the Government of India recommended for giving IIT status to University College of Engineering and University College of Technology of Osmania University and College of Engineering of Andhra University, with a rider that since there is gap between identified institutions and NTs, it is not proper to position these institutions straightaway along side of IITs and recommended for submitting Vision Documents to upgrade them to the level of IITs. Recently, the Government of Andhra Pradesh